5.

प्रश्न: राजकोषीय घाटा से आप क्या समझते हैं? इस घाटे के क्या परिणाम हो सकते हैं? इसे कम करने हेतु सरकार द्वारा किस तरह के उपाय किये गये हैं? (250 शब्द)

उत्तर:

किसी सरकार द्वारा राजस्व प्राप्तियों तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों के विनिवेश से प्राप्त धनराशि एवं दान से प्राप्त धनराशि से अधिक जो कुछ भी खर्च किया जाता है, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सरकार द्वारा लिए गए ऋण तथा रिजर्व बैंक से लिए गए उधार को राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा होने से भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजकोषीय घाटा की पूर्ति के लिए सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, जिसकी पूर्ति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अतिरिक्त मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में करती है। अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मुद्रा के प्रवाह के कारण लोगों की क्रयशक्ति बढ़ती है, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में स्फीतिक दबाव पड़ता है।

राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :-

- सरकारी विभागों का आकार छोटा करने के साथ-साथ अनेक आर्थिक उपाय किये गये हैं।
- 12 वें वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार राज्य योजनाओं के लिए केन्द्र से ऋण देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। केन्द्र केवल अनुदान देगा और ऋण की व्यवस्था राज्य स्वयं करेगा।
- राज्यों के राजस्व घाटे को कम करने से जुड़ी ऋण माफी योजना शुरू की गई है।
- राज्यों में राजकोषीय सुधारों को प्रोत्साहन देने हेतु एक प्रोत्साहन निधि की स्थापना की गई है।
- घाटे में चल रहे उद्यमों का निवेश किया जा रहा है।
- 12 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र और राज्य की ब्याज देनदारियां कम कर सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 28% और 15% पर लायी गई है।
- कर अपवंचन को रोकने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सख्त बनाया गया है तथा कई अन्य कदम भी उठाये गये हैं।

स्पष्टतः दूसरी पीढ़ी के सुधार कार्यक्रमों में राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु सरकार द्वारा जो उपर्युक्त कदम उठाये गये हैं, उसे केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा ठोस रूप से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही, राजकोषीय दायित्व कानून पारित हो जाने से राजकोषीय अनुशासन लागू हो सकता है।